### रोनाल्डो के गोल से यूर्वेटस की बड़ी जीत मिलान। क्रिस्टियानो रोनालडो के फ्री किक पर दागे गोल की मदद से युर्वेटस

ने सिरी ए फुटबॉल टूर्नामेंट में टोरिनो को 4-1 से हराया। इस मैच के दौरान जियानल्युगी बुफोन ने सिरी ए में सर्वाधिक मैचों में उतरने का रिकॉर्ड भी बनाया। रोनाल्डो ने यूवेंटस की ओर से तीसरा गोल दागा जिससे मौजूदा लीग में उनके लीग गोलों की संख्या 25 हो गई। वह लाजियो के काइरो इमोबाइल से चार गोल पीछे हैं जो शीर्ष पर चल रहे हैं। रोनाल्डो का यूवेंटस की ओर से लगभग दो सत्र में फ्री किक पर यह पहला गोल है। उन्होंने अपने 43वें प्रयास में गोल दागा। यह रोनाल्डो का फ्री किक पर 46वां क्लब गोल है। रोनाल्डो के अलावा यूवेंटस की ओर से पाउलो डाइबाला और युआन कुआड़ेडो ने पहले हाफ में गोल दागे जबिक टोरिनो की ओर से एंड्रिया बेलोटी ने गोल किया। टोरिनो के डिफेंडर कोफी जिंदजी ने दूसरे हाफ में आत्मघाती

#### ग्रेनाडा ने वेलेंसिया को बराबरी पर रोका

मैड्डि। वेलेंसिया को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में ग्रेनाडा ने 2-2 से बराबरी पर रोक दिया। इस ड्रा के साथ वेलेंसिया का लगातार तीन मैच में हार का क्रम टूट गया लेकिन टीम पिछले चार मैचों में जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। ग्रेनाडा को 86वें मिनट में फेडे विको ने फ्री किक पर गोल दागकर बराबरी दिलाई। ग्रेनाडा ने 61वें मिनट में कार्लीस फर्नांडिज के पेनल्टी किक पर दागे गोल से बढ़त बनाई लेकिन वेलेंसिया ने 63वें मिनट में मनु वालेजो और 68वें मिनट में गोंसालो गुएडेस के गोल की बदौलत स्कोर 2-

### चेल्सी ने वैटफोर्ड को 3-0 गोल से हराया

लंदन। रोस बर्कले के शानदार प्रदर्शन से चेल्सी ने रेलीगेशन का खतरा झेल रहे वैटफोर्ड को 3-0 से हराकर प्रीमियर लीग में चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इंग्लैंड के मिडफील्डर बर्कले ने 28वें मिनट में ओलिवर गिरोड के गोल में अहम भूमिका निभाई जिससे चेल्सी ने बढ़त बनाई। विलियन ने 43वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 किया। बर्कले ने इसके बाद दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम में गोल दागकर चेल्सी की 3-0 से जीत सुनिश्चित की। इस जीत से चेल्सी की टीम चौथे स्थान पर मैनचेस्टर यूनाईटेंड से दो अंक आगे जबिक लीसेस्टर से एक अंक पीछे है।

## बायर्न ने घरेलू खिताब का डबल पूरा किया

बर्लिन। बायर्न म्यूनिख ने बायर लीवरकुसेन को 4-2 गोल से हराकर जर्मन लीग के 20वें खिताब के साथ घरेलू खिताब का डबल पूरा किया। खिलाड़ियों ने हालांकि घरेलू सत्र में लगातार दूसरे खिताब का जश्न खाली स्टेडियम में मनाया। पहले ही लगातार आठवां बुंदेसलीगा खिताब जीत चुके बायर्न की ओर से रॉबर्ट लेवानदोवस्की ने दो जबिक डेविड अलाबा और सर्ज ग्नेब्री ने एक-एक गोल दागा। लेवानदोवस्की ने इसके साथ ही इस सत्र में गोल का अर्धशतक भी पूरा किया। बार्यन ने लगातार दूसरे साल लीग और कप खिताब का डबल पूरा किया है। टीम ने कुल 13वीं बार यह उपलब्धि हासिल की।

#### हार से वोल्व्स की उम्मीदों को लगा झटका

वोल्वरहैम्पटन ( ब्रिटेन )। आर्सेनल के खिलाफ प्रीमियर लीग में 0-2 की हार के साथ वोल्वरहैम्पटन की पहली बार चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को झटका लगा है। आर्सेनल की ओर से लगातार सुर्खियां बटोर रहे 18 साल के मिडफील्डर बुकायो साका ने 43वें मिनट में पहला गोल दागा जबिक स्थानापन्न खिलाड़ी एलेक्सांद्र लाकाजते ने 86वें मिनट में टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया जो निर्णायक स्कोर साबित हुआ। लीग दोबारा शुरू होने के बाद वोल्व्स की टीम ने पहली बार अंक गंवाए हैं। टीम ने इससे पहले लगातार तीन जीत दर्ज की थी। इस हार से चैंपियन्स लीग के लिए क्वालीफाई करने की वोल्वरहैम्पटन की उम्मीदों को झटका लगा है क्योंकि लीग में जगह बनाने की दौड़ में उसके प्रतिद्वंद्वियों लीसेस्टर और मैनचेस्टर यूनाईटेड दोनों ने शनिवार को जीत दर्ज की।

## सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने क्विंटन डिकॉक

जोहानसिबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के सीमित ओवरों के क्रिकेट कप्तान क्विंटन डिकॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन आनलाइन किया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक को साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया। युवा सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार मिला। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टी20 खिलाड़ी चुना गया। डेविड मिलर को प्रशंसकों के पसंदीदा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। भारत में टेस्ट पदार्पण करने वाले और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की पारी में पांच विकेट चटकाने वाले एनरिच नोर्टजे को साल का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष न्यूकमर (नया खिलाड़ी) चुना गया।

# मुझे टी-20 खेलना पसंद थाः गांगुली

बोर्ड अध्यक्ष ने छोटे फार्मेट का किया समर्थन

संवाददाता। कोलकाता

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टी-20 क्रिकेट का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि अगर वह इस दौर में खेल रहे होते तो सबसे छोटे प्रारूप की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खेल में बदलाव करते। गांगुली ने बीसीसीआई ट्विटर हैंडल के जरिए टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के सवाल के जवाब में कहा, टी-20 बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं खुद के खेल में इसके लिए बदलाव किया होता। यह आपको खुलकर खेलने की आजादी देता है। भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 एकदिवसीय खेलने वाले पूर्व कप्तान उस समय अपने करियर के आखिरी दौर में था जब इस प्रारूप को देश में अपनाया जा रहा था। उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की और फिर पुणे

वारियर्स के लिए भी खेले। उन्होंने कहा कि मुझे टी-20 खेलना पसंद था, हालांकि मैंने आईपीएल के पहले पांच साल खेले है। मुझे लगता है कि मैंने टी-20 का लुत्फ उठाया था। गांगुली ने इस मौके पर 2003 विश्श कप और लॉर्ड्स की बालकनी से टी-शर्ट लहराने की यादों को ताजा किया। भारतीय टीम गांगुली की कप्तानी में विश्व के फाइनल में पहुंची थी जबकि टीम ने 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में 326 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्व पीछा किया था। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन क्षण था। हम भावनाओं में बह गए थे, लेकिन खेल में ऐसा होता है। जब आप इस तरह का मैच जीतते हैं, तो आप और भी अधिक जश्न मनाते हैं। यह उन शानदार क्रिकेट मैचों में से एक था जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। इस जीत की विश्व कप के फाइनल से तुलना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, दोनों का अपना स्थान है। विश्व कप फाइनल मेरे लिए काफी खास हैअ हम ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया उस पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ

## कोहली के खिलाफ हितों के टकराव मामले की शिकायत की जांच कर रहा है बोर्ड

नई दिल्ली। बीसीसीआई के आचरण अधिकारी डी.के. जैन ने रविवार को कहा कि वह भारतीय कप्तान विराट कोहली के खिलाफ मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता द्वारा दायर हितों के टकराव की शिकायत की जांच कर रहे है। गुप्ता ने इससे पहले भी दूसरे खिलाड़ियों के लिए खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए थे, जिन्हें बाद में खारिज कर दिया गया था। गुप्ता ने अपनी नवीनतम शिकायत में आरोप लगाया है कि कोहली एक साथ दो पदों पर काबिज हैं। वह भारतीय टीम के कप्तान और एक ऐसे प्रतिभा प्रबंधन कंपनी के सह-निदेशक हैं जो टीम के कई खिलाडियों के प्रबंधन का काम देखती है। गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह बीसीसीआई के संविधान का उल्लंघन है जो एक व्यक्ति को कई पदों पर रहने से रोकता है। जैन ने कहा कि मुझे एक शिकायत मिली है। मैं इसकी जांच करूंगा और फिर देखूंगा कि कोई मामला बनता है या नहीं। अगर मामला बनता है तो मुझे जवाब देने के लिए उन्हें (कोहली) एक मौका देना होगा। गुप्ता ने दावा किया कि कोहली कॉर्नरस्टोन वेंचर पार्टनर्स एलएलपी और विराट कोहली स्पोर्ट्स एलएलपी में निदेशक है। इस कंपनी में अमित अरूण सजदेह (बंटी सजदेह) और बिनॉय भरत खिमजी भी सह-निदेशक है।

टीम थी। कप्तान ने कहा कि विश्व कप ऑस्ट्रेलिया को छोड कर सभी टीमों फाइनल में पहुंचना और को हराना शानदार उपलब्धि थी।

# इंग्लैंड दौरा हमारी सबसे बड़ी श्रृंखलाः केमार रोच

तेज गेंदबाज केमार रोच को लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला वेस्टइंडीज के लिए एशेज की तरह ही है और उनकी टीम पिछले साल घरेल सरजर्मी पर जीती गई ट्राफी का बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी। साउथम्पटन के एशेज बाउल में शुरूआती टेस्ट बुधवार से शुरू हो रहा है और कोरोना वायरस के कारण मार्च से निलंबित हुई सभी खेल गतिविधियों के बाद से यह पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला होगा। वेस्टइंडीज ने पिछले साल कैरेबियाई सरजमीं का दौरा करने वाली जो रूट की इंग्लैंड टीम को 2-1 से शिकस्त दी थी और रोच ने कहा कि मेहमान टीम उसी नतीजे को फिर से हासिल करना चाहती है। रोच ने कहा कि हम मजबूत थे और इस चीज ने लय बनाई। हर किसी ने प्रदर्शन किया और हम यहां भी उसी तरह के प्रदर्शन का अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। ट्राफी कैरेबियाई सरजमीं पर वापस ले जाना हमारा पहला लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जीत हासिल करना शानदार होगा लेकिन यह ट्राफी का बचाव करना है। यह हमारी सबसे बड़ी श्रृंखला है, यह हमारे लिए एशेज की तरह है इसलिए यह उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। रोच दोनों टीमों के बीच पिछली श्रृंखला में 18 विकेट झटककर सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे थे और उन्हें अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए मैन आफ द सीरीज चुना गया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गेंद पर लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है और इस 31 साल के खिलाड़ी को लगता है कि अब गेंद को चमकाना काफी मुश्किल होगा लेकिन गेंदबाज इसका तरीका ढूंढ लेंगे। उन्होंने कहा कि हां, यह सबसे कठिन चीज होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिन में कुछ गर्मी होगी और खिलाड़ियों को कुछ पसीना आएगा। हालांकि पसीना आने के लिए काफी गर्मी की जरूरत है। लेकिन मौसम भले ही कैसा भी हो, हम तरीका ढुंढ लेंगे।

# आईपीएल में रिकॉर्ड करार के बावजूद जिंदगी नहीं बदली: पैट कमिंस

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी में रिकॉर्ड राशि हासिल करने वाले आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ पैट कमिंस ने कहा है कि छह महीने बाद भी उनका जीवन नहीं बदला है क्योंकि वह कभी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो सफलता या विफलता से प्रभावित हो। दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज किमंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि में खरीदा था जिससे वह लीग के इतिहास में सबसे महंगे बिके विदेशी खिलाड़ी बने थे। पिछले साल नीलामी में इतनी अधिक राशि मिलने के बारे में पूछने पर किमंस ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मैं प्रत्एक मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूं और साथ ही कोशिश करता हूं कि किसी तरफ की सफलता या विफलता का मेरे जीवन पर अधिक असर नहीं पड़े। किमंस ने कहा कि नीलामी में इतनी अधिक राशि मिलने की ख़ुशी अब भी है और शायद जब वह खेलने के लिए जाएं तो इस भावना को पीछे छोड़ पाएंगे। निजी टी-20 लीग शुरू होने के बाद कई खिलाड़ियों ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली की तरह किमंस के लिए टेस्ट प्रारूप सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए और प्यार करते हुए बड़ा हुआ और अब भी कुछ नहीं बदला है। मुझे लगता है कि यह सबसे चुनौतीपूर्ण प्रारूप है क्योंकि यह आपके कौशल, स्टेमिना और मानसिक मजबूती की परीक्षा लेता है। आस्ट्रेलिया के लिए 21.82 की प्रभावी औसत से 30 टेस्ट में 143 विकेट चटकाने वाले कमिंस ने कहा, प्रत्एक टेस्ट जीत काफी संतोषजनक होती है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने अपने खिलाडि़यों को आउटडोर ट्रेनिंग की स्वीकृति दे दी है और इस तेज गेंदबाज ने नेट पर अभ्यास शुरू कर दिया है लेकिन उन्होंने कहा कि शीर्ष मैच फिटनेस हासिल करने में समय लगेगा। कमिंस ने कहा कि पूर्ण गति और फिटनेस हासिल करने में कुछ महीनों का समय लगेगा लेकिन भाग्य से हमारे पास समय है। हमने दो हफ्ते पहले गेंदबाजी शुरू की। इसलिए जब हम शुरुआत करेंगे तो उसके लिए तैयार रहेंगे। किमंस का मानना है कि टी-20 प्रारूप के साथ शुरुआत करना सही रहेगा और संभवत: टेस्ट मैचों (अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और फिर भारत के खिलाफ श्रंखला) के समय में तक पांच दिवसीय क्रिकेट की कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाएंगे।

## कैब कार्यालय सात दिन के लिए बंद

**कोलकाता**। ऐतिहासिक ईंडन गार्डन्स मैदान के एक अस्थाई कर्मचारी के कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने के कारण बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के मुख्यालय को रविवार को सात दिन के लिए बंद कर दिया गया। कैब के अध्यक्ष अविषेक डालिमया ने बयान में कहा कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग में अस्थाई तौर पर काम करने वाला चंदन दास शनिवार को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने कहा कि उसे चारनोक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि वह एक हफ्ते से कैब कार्यालय नहीं आया था, मेडिकल समिति में शामिल प्रतिष्ठत डॉक्टरों की सलाह पर हमने सभी को अगले सात दिन पर कैब कार्यालय में आने से बचने को कहा है।

#### भारत में बास्केटबॉल लीग की जरूरतः भृगुवंशी

**नई दिल्ली**। भारत की बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भुगुवंशी का कहना है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और उन्हें लगता है कि पेशेवर लीग से राष्टीय खिलाडियों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ ने भृगुवंशी को फिर से अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है और उन्हें उम्मीद है कि तीसरी बार अनुशंसा किए जाने के बाद वह इसे हासिल करने में सफल रहेंगे।

# मेंडिस की गाड़ी से दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, गिरफ्तार

श्रीलंका के क्रिकेटर कुसाल मेंडिस को रविवार को गिरफ्तार किया गया जब उनकी गाड़ी से टकराकर एक साइकिल सवार की मौत हो गई। यह दुर्घटना कोलंबो के उपनगर पनादुरा की ओल्ड गॉल रोड पर हुई जिसमें 64 साल के साइकिल सवार की मौत हो गई। मेंडिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जबकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मेंडिस की कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी जो गोकारेला का रहने वाला था। दुर्घटना चार साल की जेल की निलंबित सजा में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और मिली थी।

अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने क्रिकेटर की एसयूवी को जब्त कर लिया है और जांच कर रही है कि कहीं वह नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहा था। 25 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज मेंडिस ने 44 टेस्ट और 76 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। वह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे जिसने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद ट्रेनिंग शुरू की है। श्रीलंका के स्पिनर कौशल

लोकुराची को भी 2003 में महिला राहगीर को गाड़ी से टक्कर मारने पर

#### बोर्ड अध्यक्ष एटीके-मोहन बागान के एक निदेशक के रूप में नामित

कोलकाता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली को एटीके और मोहन बागान को विलय कर बनी इंडियन सुपर लीग की नई टीम का एक निदेशक नामित किया गया है। मोहन बागान क्लब में 80 प्रतिशत की हिस्सा हासिल करने वाले चेयरमैन संजीव गोयनका के नेतृत्व में 10 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें क्लब के नाम, जर्सी और लोगो (प्रतीक चिन्ह) को अंतिम रूप दिया जाएगा।खबर की पुष्टि करते हुए टीम के सह-मालिक और एक निदेशक उत्सव पारेख ने पीटीआई-भाषा को बताया, गांगुली टीम के सह-मालिकों में से एक हैं और निदेशक बनने के शत

## गुरु पूर्णिमा पर सचिन ने तीन गुरुओं को किया याद

भाषा। नई दिल्ली

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर उनके करियर को आगे बढाने में अहम योगदान देने वाले तीन गुरुओं को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। तेदलकर ने एक वीडियो साझा उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ हमेशा शुक्रगुजार रहुंगा। क्रिकेट के भले ही उस वक्त शारीरिक रूप से कभी जल्दबाजी मत करना।

इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में मेरे साथ नहीं रहते थे लेकिन शामिल तेंदलकर ने इस वीडियो में कहा, मैं जब भी बल्ला उठाता हूं तो मेरे जेहन में तीन लोगों के नाम आते हैं, जिनकी मेरी जिंदगी में खास अहमियत है। मैं आज जो भी हूं वह इन तीन लोगों की वजह से ही हूं। सबसे पहले मेरे भाई, जो मुझे

मानसिक रूप से वह हमेशा मेरे साथ रहते थे। मैं जब भी बल्लेबाजी करने गया, उनके साथ ही गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का शतक लगाने वाले इस पूर्व दिग्गज ने कहा, जब बात आचरेकर सर की आती है तो मैं उनके बारे में क्या करते हुए लिखा, गुरु पूर्णिमा पर, मैं रमाकांत आचरेकर सर के पास ले कहूं ? उन्होंने मेरी बल्लेबाजी पर कर गए। उन्होंने बड़े भाई अजित अपना काफी वक्त दिया। उन्होंने तेंदुलकर की योगदान की सराहना इसके बाद आपने पिता का शुक्रिया देने की सीख दी और प्रेरित किया। मैं करते हुए कहा, मैं जब भी करते हुए कहा कि आखिर में मेरे पिता हालांकि इन तीन महानुभावों का बल्लेबाजी करने जाता था तो वह जी, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा कि

# साल डेढ़ साल में महंगी हो सकती हैं फोन कॉल व इंटरनेट की दरें

दुरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढाया जा सकता है। किफायत के बारे में भी सोचना होगा, ईवाय ने यह अनुमान व्यक्त किया है। लेकिन बाजार में टिके रहना ईवाय के लीडर (उभरते बाजारों की प्रौद्योगिकी, मीडिया एवं मनोरंजन और दूरसंचार) प्रशांत सिंघल ने कहा सकती हैं और पहली वृद्धि अगले छह कि दरों में तत्काल वृद्धि अभी के महीने में भीहो सकती है। सिंघल ने हिसाब से उचित नहीं लग रहा है। यह कहा कि यह नियामकीय हस्तक्षेप के अगले 12 से 18 महीने में दो दौर में माध्यम से होता है या दूरसंचार उद्योग किया जा सकता है तथा पहली वृद्धि अगले छह महीने में की जा सकती है। है कि दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय उन्होंने से कहा कि दरों में वृद्धि स्थिति शुल्क वृद्धि को अपरिहार्य बना अपरिहार्य है। उपभोक्ताओं के लिए रही है।

दुरसंचार खर्च ठीक-ठाक कम है और अगले छह महीने में दरों में वृद्धि की जा सकती है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह होगा ही, लेकिन जितना जल्दी हो उतना बेहतर। उन्होंने कहा कि कंपनियों को आर्थिक स्थिति तथा सुनिश्चित करने के लिए 12 से 18 महीने में दो बार में दरें बढ़ाई जा खुद ही यह करती है लेकिन यह स्पष्ट

विलंब से भुगतान पर जुर्माने के फैसले से वेंडरों को समय पर भगतान मिल सकेगा: जीईएम

नर्ड दिल्ली। वित्त मंत्रालय द्वारा जीईएम प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उत्पाद बेच रहे वेंडरों को भगतान में विलंब करने वाले सरकारी विभागों और एजेंसियों पर एक प्रतिशत का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तल्लीन कुमार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस फैसले से वेंडरों विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को समय पर भगतान स्निश्चित हो सकेगा। पिछले सप्ताह व्यय विभाग ने घोषणा की थी कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफॉर्म से माल एवं सेवाओं की खरीद करने वाले सरकारी विभागों को वेंडरों को विलंब से भुगतान पर एक प्रतिशत का ब्याज देना होगा। कुमार ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि जीईएम के विक्रेताओं की एक सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि सरकारी खरीदार उन्हें समय पर भूगतान नहीं करते हैं। कुमार ने कहा कि अब एक ऐतिहासिक कदम से वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल कर दिया है। जीईएम के जिए अपने उत्पाद बेचने वाले वेंडरों को अब समय पर भुगतान मिल सकेगा। सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि वेंडरों विशेषरूप से एमएसएमई क्षेत्र को उनका भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए।

#### रिलायंस की विमानन ईंधन स्टेशनों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने की योजना

संवाददाता। नई दिल्ली

अखपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की योजना अपने विमानन ईंधन डिपो की संख्या में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की है। इस कारोबार का बड़ा हिस्सा अभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास है और आरआईएल इसमें अधिक बाजार हिस्सेदारी पाना चाहती है। आरआईएल ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि विमानन क्षेत्र में पिछले 52 महीनों में लगातार हासिल की गई दो अंकों की वृद्धि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय भले ही रुक गई हो , लेकिन भारत अगले पांच वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाले विमानन बाजारों में बना रहेगा।

## सरकारी बैंकों की पूंजी की जरूरतों की समीक्षा कर सकता है वित्त मंत्रालय

बैंकों की पंजी की आवश्यकता का आकलन कर सकता है, क्योंकि उस समय तक खराब ऋणों में बढ़ोतरी के बारे में आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है। इस कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसा होने की स्थिति में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत बैंकों को एनपीए के लिए किया जाने प्रावधान बढाना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि यदि आरबीआई कोरोना वायरस महामारी

नर्ड दिल्ली। वित्त मंत्रालय सितंबर पुनर्गठन के अनुरोध को स्वीकार कर तिमाही के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लेता है, तो बैंकों को राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि कर्ज की किस्तें चकाने से राहत की अवधि अगस्त में समाप्त हो रही है। उसके बाद ही एनपीए को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ऐसे में एक बार जब दूसरी तिमाही के आंकडे स्पष्ट हो जाएं, पंजी की आवश्यकता की समीक्षा तभी करना उचित होगा। बैंकिंग क्षेत्र के कारोबारी तथा उद्योग संगठन सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक का कहना है कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सरकारी बैंकों को सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत पट्टेगी।

## महंगा नहीं. अपने बजट के अनुकुल घर खरीदना चाहते हैं लोग

चेन्नई। कोविड-19 की वजह से लागु लॉकडाउन के बीच लोगों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करना पड रहा है। रीयल्टी कंपनियों का कहना है कि ऐसे में खरीदार अपनी जेब अधिक ढीली करने को तैयार नहीं हैं, और वे लक्जरी यानी महंगे मकानों के बजाय बजट अनुकूल घरों की खरीद करना चाहते हैं। अक्षय होम्स लि. के संस्थापक टी चिटटी बाब ने कहा कि पहले जो लोग पेइंग गेस्ट के रूप में रहना चाहते थे, अब वे अपने बजट में अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इस महामारी ने डेवलपर्स और लोगों के लिए काफी अवसर पैदा किए हैं। बाबू ने कहा कि अब ग्राहकों को अपने घर की जरूरत समझ आ गई है।

#### पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋग सीआईएन : एल65929डीएल1947पीएलसी001240 ; ई—मेल : pnbfinanceindustries@gn पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–11 फोन नंबर : +91-7303495375 ; वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com

गया है, ताकि वे उपयुक्त कार्यवाही कर सकें।

सूचना

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण द्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) के साथ पवि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली. 201 और उसके संशोधन (नों) ('आईईपीएफ नियमावली') के अनुसरण में कम्पनी द्वारा ऐसे समी शेयर, आईईपीएए ायमावली के अनुसार, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिए जाएंगे, जिन संबंध में शेयरधारकों द्वारा सात लगातार वर्षों अथवा अधिक से लामाश की मांग नहीं की गई है। संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचनाएं, कम्पनी में उपलब्ध उनके अंतिम ज्ञात पते पर, प्रेषित की चुकी हैं, जिसमें अन्य के साथ आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के भागी शेयरों का विवरण उपलब्ध करार

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना मांगा नहीं गया लामांश 03 अगस्त, 2020 को अथवा प् मांग लें, जिसमें असफल रहने पर उनके शेयर नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ अंतरित कर दिए जाएंगे। कम्पनी आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के मागी शेयरों का विवरण अपन वेबसाइट www.pnbfinanceandindustries.com पर अपलोड कर चुकी है।

संबंधित शेयरधारक वेब प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आवेदन देकर अपने शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापर प्राप्त करने के हकदार हैं, जैसाकि उपरोक्त नियमावली में निर्घारित किया गया है तथा जोकि आईईपीए की वेबसाइट नामतः www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

यदि शेयरघारकों को उपरोक्त के विषय और आईईपीएफ नियमावली के बारे में कोई संदेह है, वे अपने प्ररू nceindustries@gmail.com पर भेज सकते हैं अथवा स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट), डी-153ए, प्रथम तल, ओख parveen@skylinerta.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

## कर्ज नहीं चुका पा रही कंपनियों को धन जुटाने की सुविधा देंगे सेबी के नए नियम नर्इ दिल्ली। बाजार नियामक सेबी के खोए बिना प्रवर्तकों को वित्तीय तनावग्रस्त सुचीबद्ध कंपनियों के

संशोधनों से कंपनी पर नियंत्रण को में मूल्य निर्धारण में ढील दी थी और आईबीसी ढांचे के तहत नहीं गए हैं। | गया।

कई संशोधन करने के बाद वित्तीय सकती है। यहां तक कि अगर उन्हें दबाव में पड़ी कंपनियों के प्रवर्तकों के कोई ऐसे निवेशक मिलते हैं जो लिए निवेशकों को जुटाना और शेयर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो भी कंपनी की सही कीमत तय करने में में प्रवर्तकों की भूमिका कम भले हो सहिलयत होगी। बाजार विशेषज्ञों का लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी। कहना है कि नए दिशानिर्देशों से विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे लचीलेपन

तरजीही शेयर जारी करने के नियमों में निवेशकों को लाने में मदद मिल तरजीही आवंटन के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनाने का रास्ता साफ किया था। सेबी ने यह सुनिश्चित किया कि तनावग्रस्त कंपनियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का आसानी से लाभ उठाया जा सके और इसके लिए तनावग्रस्त कंपनी की अर्हता पाने के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूहों को के कारण प्रवर्तक इन दिशानिर्देशों के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए निवेशक आकर्षित करने में आसानी माध्यम से पुनर्गठन करना पसंद कर गए। दिशानिर्देश उन कंपनियों के होगी और उन्हें दिवाला संहिता की सकते हैं क्योंकि ए आईबीसी के लिए तरजीही निर्गम के जरिए धन प्रक्रिया की तरह पूरी तहर कंपनी से मुकाबले बेहतर और तेज विकल्प है। जुटाने को आसान बनाते हैं, जो निर्वासित भी नहीं होना पड़ेगा। सेबी ने अपने 22 जून के दिशानिर्देशों वास्तव में तनावग्रस्त हैं, लेकिन

सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.37 लाख करोड़ बढ़ा

नई दिल्ली। सेंसेक्स की शीर्ष दस कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह।,37,508.61 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सबसे अधिक लाभ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहीं। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 850.15 अंक या 2.41 प्रतिशत के लाभ में रहा।

समीक्षाधीन सप्ताह में टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 31,294.89 करोड़ रुपये बढ़कर 8,25,149.40 करोड़ रुपये पर पहुंच

## बड़े आयात वाले 15 उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करे भारत: एसोचैम

नर्ड दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम मानना है कि आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को 15 बड़े आयात वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देश में उनके उत्पादन की क्षमता बढ़ानी चाहिए। उद्योग मंडल ने ऐसे 15 उत्पादों को चिहिनत करते हुए कहा है कि इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाकर हम दो-तीन साल में आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को पा सकते हैं। इन उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, लौह-चादर, अलौह धातु, वनस्पति तेल आदि शामिल हैं। आंकडों से पता चलता है कि गैर-तेल आयात खंड में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का हिस्सा सबसे अधिक है। देश के आंशिक लॉकडाउन के बावजूद मई में भारत ने 2.8 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात किया। एसोचैम ने एक नोट में कहा, उद्योग के सामान्य परिचालन के दिनों यह आयात एक महीने करीब पांच अरब डॉलर रहता है। इस पर एक बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हालिया उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और चैपियनों को प्रोत्साहन पासा पलटने वाला साबित हो सकता है।

# 'There's a need to have a specific policy for unorganized workers'

gyan.v@livemint.com NEW DELHI

here is a need to have specific policy for unorganized workers, which cannot be relegated to a future date, says Bhartruhari Mahtab, chairperson of the standing committee for Labour. In an interview, the senior leader of the Biju Janata Dal (BJD) also said the Inter-State Migrant Workers Act, 1979, does not protect the interests of migrant workers in anyway and has become redundant. The country seems to have woken up to the miseries of migrant workers, when, bereft of food, shelter, and employment, they started walking back to their villages during the lockdown, he added. Edited

The labour committee's report on the Code on Social Security Bill, 2019, is to be submitted at the beginning of monsoon session. Do you think the committee will be able to submit it's report on time?

Our attempt is to submit the Report on

Social Security Code in time. Yes, there has been some difficulty in collating information from domain experts but whatever queries

were there have been answered. I have already asked our secretariat to draft the report and I believe it would be ready by a week or so.

What are the main focus areas of the committee? How do you look at the urgency among state governments for the Bill to be presented after the recent migration crisis?

Social Security Code deals with a vast subject. Earlier, the thrust was only on organized labour. Now we have brought in, along with the organized, the unorgan-



**CONVERSATION** 

**BHARTRUHARI MAHTAB** 

ized labour force. The government, of course, has a number of programmes for common citizens, different sets of people or groups for their health services. and

pension programmes, but for workers, that too the unorganized, there is a need to have a specific policy that cannot be relegated to a future date. Our committee is seriously thinking about it and I hope it will find place in our report.

As there are only 9.4% of workforce in the organized sector and around 90% workforce in the unorganized sector, it demonstrates that there is a need to recognize that the present labour laws are unable to look into the interests of the labour force. Our major attempt is to address and correct this dichotomy.

The nearly three-month-long lockdown has pushed migrant worker rights into the spotlight. There is a growing demand for a separate policy or law for migrants. What are your views?

The lockdown has heightened the plight of the migrant labour force. There is a law, the Inter-State

Migrant Workers Act, 1979, but it didn't protect the migrant workers' interest in anyway. Rather during last 40 years, it had become redundant. It was during the lockdown when migrant workers, bereft of food, shelter, employment started walking back to their villages that the country seems to have awakened up to their miseries. Our standing committee on labour had drawn the attention of the Union government in last February in our report on "The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code" towards the importance of migrant workers, especially inter-state migrant labour.

government, we were assured that migrant workers would be treated as contract labourers and all those benefits that they are entitled to would be provided to them, including safety and health. Now as social security measures there is a necessity to ensure habitable shelter to the migrant workers. Further we are thinking of suggesting portable social security coverage to all the inter-state migrant workers so that they get all the benefits that they are entitled to as they get in their

returned to their villages in iust Uttar Pradesh, Bihar, and Jharkhand. How will generating post this crisis?

We have recommended in our earlier report that a worker-friendly initiative should be taken and that the definition of



All queries related to the Code on Social Security Bill, 2019, have been answered. Our report would be ready in a week or so.

**BHARTRUHARI MAHTAB** BJD leader and chairperson of the

parliamentary standing committee on labour

inter-state migrant workers should be broadened by including "employer" with "contractor". There is also a need for proper registration of migrant workers in both source and destination states. This will help in proper implementation of the One-Nation-One-Ration Card Scheme.

Relating to providing gainful employment to those millions of workers who have returned to their states, it is imperative on the part of those state governments to map their skill and try to engage them to earn their livelihood.

The decision of the Union government and the state governments to allow industries to function for longer hours and make labourers work for longer hours

was opposed by some of the Opposition-ruled states. What is your opinion about this, in view of the economic crisis during lockdown being a big concern?

The standing committee on labour has recommended in its report that the provision for providing a maximum 8 hours of work per day should be incorporated in line with the International Labour Organization (ILO) convention. It must be kept in mind that this decision was taken 100 years ago. In the 21st century there are certain industries like textile

where technology has improved and workers want to work for more hours.

Similarly, a certain class of workers such as journalists and audio visual workers and people working in the software industry, the hospitality sector, and motor transport, do not work 8 hours at a stretch and their working hours are spread out. Therefore, we have suggested that due care be taken while prescribing a maximum 8 hours of work per day mandatorily. Yet we have said the limit on overtime hours should be prescribed approximately. What we have suggested is to bring in little flexibility in working hours. Nothing should be done which may lead to exploitation of workers.

The ongoing situation is unprecedented and has affected the function-

ing of Parliament and its committees. Do you think it is time to relook at the way standing committees have func-

tioned and both the Lok Sabha and the Rajya Sabha should allow online functioning of commit-

> Yes, the unprecedented situation demands unprecedented solutions. The situation is not normal. Accordingly, steps should be taken as it has been done in many other countries that have parliamentary democracies. There are two aspects to which I would like to

> First, there has been always a view expressed in some quarters that the proceedings of the standing committees should not be in camera and be open for public observation as is happening in almost all developed democratic countries. As committee meetings are mini-Parliament in session, I feel there should not be any confidentiality in its functioning. Of course, certain deliberations can be done in camera, maintaining

the confidentiality in matters of national security and public order, but generally the standing committee needs to be made open now.

Second, if we do away with the confidentiality clause, we can conduct our standing committee meetings virtually. Parliament sessions can also be conducted in a hybrid system, where for a quorum, at least 10% of the members can be present in the House and the rest can join by videoconferencing, thus adhering to social distancing rules.

Several states have brought in changes to labour laws against the backdrop of the recent reverse migration. Is there a need for more standardization of labour laws across the



Migrants need to be registered in source and destination states for implementation of one nation, one ration card scheme.

> country or do you think federal autonomy strengthens such systems?

> It came to our notice during the first month of the lockdown that some states had brought in drastic changes in labour laws. Every change, of course, did not relate to migration of labour. Some changes have been made to do away with bottlenecks and some were forward look-

> As the labour force in Assam or Kerala who work in plantations have a different work culture and so do the workers of Punjab. We cannot have one system fits all here. Therefore, every state is empowered to make provisions for labour keeping their actual need in view. However, as a nation, there has to be a policy guideline, which is to be adhered to by every state.



Read Anil Padmanabhan's earlier columns at

# HIT THE RESET, IT'S TIME TO LOOK AT A PANDEMIC BUDGET

ast week, the Union government extended the programme

to distribute free foodgrains to 800 million citizens by

another five months to November; this is estimated to cost

the exchequer, already committed to bankrolling a ₹1.7 trillion

relief package to mitigate the impact of the covid-19 pandemic

on livelihoods of the poor, an additional outgo of 390,000 crore.



**Dubey** knew about arrested aide tells

In a separate development later in the week, the Kerala government increased fares of public transport by 25% to stem mount ing losses as the pandemic kept most people off the roads. The two developments, seemingly unlinked, are actually different sides of the same coin: they reflect the fiscal shock and consequences accruing from mega disruptions like the covid-19 pandemic. It forced the government to implement a nationwide lockdown to contain the spread, knocking the bottom out of the economy. Not only did revenue receipts shrink to record lows,

expenditure commitments skyrocketed as both the Union and state governments rushed to protect both lives and livelihoods. The fiscal shock has been unprecedented. If this was a one-off event, it would be cause for worry, not despair. Unfortunately, what we are discerning is a risk pattern, of a kind we have known but never acknowledged. Consequently, this kind of risks will have to be assessed, priced and factored into

begun to do to cushion against a health shock emanating from the growing incidence and spread of non-communicable diseases. In short, public policy in countries, particularly India, will need to start reflecting mitigation measures to cushion against risks arising from this 'new-normal'. Easier said than done. It means junking the accepted mindset and retuning public policy to

public policy -- something very similar to what individuals have

embrace a new paradigm. Remember covid-19 is just one among many emerging threats. To cite a few: extreme weather conditions have started occurring in frightening regularity (According to the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, extreme weather incidents have begun to spike, from 71 in the 1970s to 224 in the 1990s and  $350\,\mathrm{in}\,\mathrm{the}\,\mathrm{first}\,\mathrm{decade}\,\mathrm{of}\,\mathrm{the}\,\mathrm{millennium.}$ ), terrorist attacks are

Public policy

start reflecting

against covid-

induced risks

mitigation steps

will need to

commonplace and last but not the least, countries need to fear getting into prolonged low-intensity conflicts with troublesome neighbours (like what India has ongoing with Pakistan on the Western border).

> It is tragic that it has taken a once-ina-century pandemic originating in Wuhan, China to put the spotlight on this trend of growing risks from such disruptions. Covid-19 has unequivocally demonstrated that geography is

no defence in a globalized world against vector-borne infectious diseases. In the last two decades, we have had two pandemics and three epidemics sweep the world—an average of one outbreak every five years. Not only are they causing increased morbidity and mortality, the economic damage is accruing through multiple channels -- exactly why they are so devastating.

In the Indian context, the challenge is that much more acute. The legacy of public policy neglect of the last seven decades means the country is bereft of any worthwhile social or economic infrastructure-leaving both lives and livelihood extremely vulnerable to such unpredictable risks. Consequently, that much more heavy-lifting will have to be required to pull the country up by its bootstraps.

In the short run, there is no option other than continuing to fund social safety nets—like providing free foodgrains—for the poor and vulnerable. But in the medium to long term, the country has to explore the option of hitting a mindset reset and prioritizing delivery of basic health, social and economic infrastructurethe best safety net for people to absorb the first round impact of disruptions like covid-19—even while creating a risk cover to deal with a mega disruption.

Undoubtedly, this crisis offers an opportunity laced with risk. On the other hand, status quo is no answer; the response has to be proactive and not defensive.

Prime Minister Narendra Modi has earned enormous social capital by winning back-to-back general elections; he has also shown appetite to pursue out-of-the-box solutions. The big question is whether he will expend his social capital on such a big bet. Only time will tell.

Anil Padmanabhan is managing editor of Mint and writes every week on the intersection of politics and economics.

Comments are welcome at anil.p@livemint.com



To get your MINT copy, give a missed call on

or write to us at

035039 or visit



#### छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावास भवन, सेक्टर–19ं, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) //सर्व संबंधित को सूचना //

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा-संशोधित) के तहत् सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट बैंकुठ सीमेंट वर्क्स), पोस्ट-बैंकुंठ, जिला-रायपुर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम खरोरा एवं केसला, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर में प्रस्तावित केसला लाईम स्टोन माईन ब्लॉक लीज क्षेत्र 108.335 हेक्टेयर में लाईम स्टोन उत्खनन क्षमता-3.0 मिलियन टन/वर्ष ( ROM ) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति/सुझाव/विचार/टीका टिप्पणी, इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल. व्यवसायिक परिसर, कबीर नगर, रायपुर के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 07/08/2020 को समय दोपहर 12:00 बजे से परियोजना स्थल-स्पोर्ट स्टेडियम उप तहसील खरोरा के पास, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर में नियत की गई है। यह भी सूचित हो किः

- 1. लोक सुनवाई के दौरान सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को फिजिकल/सोश्ल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 2. लोक सुनवाई में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जावेगा तथा समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3. लोक सुनवाई स्थल पर सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था कम से कम 02 मीटर
- 4. कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशो का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 14 सितम्बर, 2006 (यथा-संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन/पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा सी.डी. (साफ्ट कॉपी) डायरेक्टर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय. जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय ( डब्लू.सी.जेड ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कार्यालय कलेक्टर रायपुर, जिला-रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत. जिला-रायपुर, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-रायपुर, कार्यालय मख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत खरोरा, जिला-रायपर, सरपंच, ग्राम पंचायत केसला, ग्राम-केसला, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यवसायिक परिसर, कबीर नगर, जिला-रायपुर एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर में रखी गई है।

> छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

#### CIN No. U63023RJ2010SGC033489 e-Bid Notice e-Bid are invited for transportation work of Food Grain & Sugar under P.D.S. Bikaner District for one year from the date of agreement. The Bid shall be submit only through online tendering system at concerned district on the webs www.eproc.rajasthan.gov.in as detailed below Name of the Service Online bid date Transportation work for Food 03-07-2020 10-07-2020 UBN No. FCS2021SLOB00015 Manager Civil Supplies Raj.Samwad/C/20/1812

### RAIGARH MUNICIPAL CORPORATION, RAIGARH (C.G.)

Phone No.:- 07762-222911, Fax No.:- 07762-222923 Email:- nraigarh@ymail.com Website - www.nagarnigamraigarh.com

Letter ID, 513/PWD/RMC/2020

#### Raigarh, Date: 03/07/2020 **RFP NOTICE (Second Call)**

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR SELECTION OF SERVICE PROVIDER FOR RUNNING MMU UNDER MUKHYA MANTRI SLUM SWASTHYA YOJNA FOR RAIGARH CITY

Through this notice Raigarh Urban Public Service Society, Raigarh, Nodal office Municipal Corporation Raigarh, herein after referred to as "Raigarh Mobile Medical Unit Service Procuring Agency (MMUSPA)' invites proposal through online Electronic Chhattisgarh Government Procurement System (eGPS) https:// eproc.cgstate.gov.in for selection of service provider for running MMU under Mukhya Mantri Slum Swasthya Yojna For Raigarh City. Interested Bidders should provide information demonstrating that they have the required qualification and relevant experience to perform the relevant tasks. Bidder may also download the Bid enquiry documents (a complete set of document is available on website) from the web site (www/https://eproc.cgstate.gov.in) or www/http://uad.cg.gov.in or www.nagarnigamraigarh.com

Last Date of Bid Submission - 16-07-2020, 5:30 PM Last Date of Physical Submission - 17-07-2020 5:30 PM

**Nodal Officer Raigarh Urban Public Service Society** Raigarh (C.G.)

#### कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड. वृत्त पी.एण्ड एम., जयपुर

बिड आमंत्रण स्चना संख्या-02/2020-21 इस वृत्त के अधीन खण्ड-टोंक, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय एवं वृत्त-जयपुर के अधीन ड–भरतपुर के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन बिंड ई–प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम रं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत बिडर्स से आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in, एव www.agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb पर भी देखा जा सकता है राज.संवाद / सी / 20 / 1822

#### PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED CIN: L65929DL1947PLC001240; Email: pnbfinanceindustries@gmail.com

Regd office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Tel No.: +91-7303495375, Website: www.pnbfinanceandindustries.com NOTICE Trsanfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Members are hereby informed that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013

read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfe and Refund) Rules, 2016 and amendment(s) thereto ("IEPF Rules"), all shares in respect o which dividend has not been claimed by the shareholders for seven consecutive years o more shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protectic Fund (IEPF) in terms of IEPF Rules.

Individual notices to respective shareholders have been sent at their latest addresse available in the Company records, inter alia, providing the details of shares liable to be transferred to IEPF for taking appropriate action.

The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend on or before August 03, 2020, failing which their shares shall be transferred to IEPF as per the procedure rescribed in the Rules. The Company has uploaded details of such shares due for transfe DIEPF on its website www.pnbfinanceandindustries.com.

The concerned shareholders would be entitled to claim the shares from IEPF authority b making an application in web form IEPF-5, as prescribed under the aforesaid rules and the ame is available on IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.

n case the shareholders have any queries wrt subject matter and IEPF Rules, they ma end their queries to the Company at mail id: pnbfinanceindustries@gmail.com or ca contact Skyline Financial Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent), D-153A st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Phone: 011-26812682/83 nail: parveen@skylinerta.com.

For PNB Finance and Industries Limited

Date . July 04, 2020

Shweta Saxena